निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात संवर्धन एककों द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा न किया जाना

*87. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात संवर्धन एककों ने सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ से अपने निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान ऐसे कितने एककों के खिलाफ कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि निर्यात दायित्व को पूरा न कर पाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को बदनामी उठानी पड़ रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) निर्धारित मूल्यवर्धनों के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकने के परिणामस्वरूप, निर्यात दायित्व पूरा करने के मामले में कुछ निर्यातोन्मुखी एककों की न्यूनतायें तो बताई गई हैं किन्तु, यह कहना सही नहीं है कि यह दायित्व सरकारी अधिकारियों की सांठ-गाँठ से पूरा नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) निर्यात दायित्व को पूरा किये जाने की नियमित आधार पर मानीटरिंग की जाती है । वर्ष 1993-94 के दौरान विदेश व्यापार महा-निदेशालय के प्रवर्तन प्रभाग द्वारा 15 मामलों में कार्यवाही की गई है ।

(घ) निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात संसाधन जोन एककों द्वारा निर्यात संवि-दाएं पूरी नहीं किये जाने के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिकूल प्रचार हुआ हो ।

Reviving Reduced Quota of Sugar to Ration Card holders in the country

*89. DR. RANBIR SINGH :
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that supply of sugar through PDS was reduced to 200 gm. per unit by States including the National Capital territory of Delhi due to less allocation of sugar from Central Pool; and

(b) if so, whether Government are going to revive the quota of sugar and if so, by when?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Decisions on monthly entitlement of Commodities under the Pubic Distribution System (PDS) for consumers are taken by the State Governments/UT Administrations as the matter is under their administarative jurisdiction. Levy sugar allocations to States/UTs for the PDS is generally made on a uniform norm of 425 gms. per capita monthly availability to the projected population as on 1-10-86. The Central Government has not received any report that supply of sugar through PDS has been reduced to 200 gms. per unit by any State/UT including NCT of Delhi.

(b) Does not arise.

Journalists' Wage Board

*90. SHRI GURUDAS DAS GUPTA
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Wage Boards for journalists and the newspaper employees constituted by the Central Government on 2nd September, 1994, have started functioning;

(b) if not, what are the reasons therefor; and